

भारतीय शिक्षा को बदलने में NEP 2020 की भूमिका का एक शैक्षणिक अध्ययन

डॉ० दिल्लीपत सहा० प्रोफेसर

मोतीवाई राजाराम महाविद्यालय गरौठा (झाँसी)

सारांश, प्रस्तुत शोधपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों की भूमिका निर्धारित करने का प्रयास करता है। हालाँकि, NEP में इन संभावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया है। हालाँकि, गुणवत्तापूर्ण संग्रह डिजिटल संसाधनों वाले पुस्तकालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचार करना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार, कई शैक्षिक स्तर पेश किए जाएँगे, जिनमें मौलिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा चरण, शोध चरण और आजीवन सीखने का चरण शामिल है। NEP ने राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने सहित कई क्षेत्रों में पुस्तकालयों के महत्व पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, निश्चित लाइब्रेरियनशिप का अभ्यास करके, पुस्तकालय पेशेवरों को नए क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिसमें वे सुधार कर सकते हैं और उच्च शिक्षा विद्वानों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इस समीक्षा के लेखक ने इस बारे में बात की कि कैसे सरकार और विश्वविद्यालय NEP के लिए पुस्तकालयों में अपनी भूमिकाएँ बदल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रबंधन पुस्तकालयों को छात्र और अनुसंधान सहायता के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और साथ ही एक संरक्षक भूमिका भी निभानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पुस्तकालय, पुस्तकालयों की भूमिका, एनईपी, उच्च शिक्षा, एनईपी में सरकार की भूमिका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा और 21 वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए महत्व दिया गया है। यहां देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध पुस्तकों के आकर्षण और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पुस्तकालयों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। प्रभावी और कुशल पुस्तकालय सेवा के लिए पुस्तकालयों के विकास के लिए अच्छी तरह से वित्त पोषण योजनाएं आवश्यक हैं। पुस्तकालय सेवाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन भी दुनिया भर में ज्ञान का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षणिक संस्थान और पुस्तकालयों के बीच एकीकरण और सहयोग पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार में बदलाव लाता है। शैक्षिक प्रणाली की प्रगति के लिए पुस्तकालयों की भूमिका को समझना आवश्यक है

मुख्य शब्द, NEP, पुस्तकालय, डिजिटलीकरण, स्कूल, कक्षा, फीडबैक, व्यावसायिक शिक्षा आदि।

परिचय, प्रत्येक देश का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। शिक्षण पद्धति पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत सहायक होता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अच्छा शिक्षण वातावरण मिलता है। शिक्षा

देश और पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। सरकार को लोगों के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। दुनिया हर क्षेत्र में बदल रही है। प्रगति हासिल करने के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी हैं। 34 वर्षों के बाद आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। स्कूली और उच्च शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और 10वीं और 12वीं बोर्ड का महत्व अब कम होने जा रहा है। स्कूली शिक्षा को 102 के बजाय 5334 के रूप में संरचित किया गया है। अब छठी कक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी इसलिए 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के दोनों रूपों को अनुशासनात्मक ढांचे से बाहर निकालकर अंतःविषय और समन्वित बनाया गया है। इंजीनियरिंग और संगीत दोनों को एक साथ लेकर उच्च शिक्षा पूरी की जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्देश्य प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संक्षिप्त जानकारी देना
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुस्तकालयों की बदलती भूमिका का वर्णन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली बनाने का विजन है जो हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी रूप से बदलने में सीधे योगदान देती है।
- 4 नीति का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके इसे प्राप्त करना है।
- 5 नीति का एक प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा पर राज्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4% से बढ़ाकर 6% करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग शिक्षा क्षेत्र का सर्वोच्च निकाय होगा और इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करेंगे। भारतीय छात्रों की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन भारत में शोध की कमी के कारण, यह गुणवत्ता भारत को लाभान्वित नहीं करती है भारतीयों की गुणवत्ता को पहचानते हुए भारत ऐसे मेधावी छात्रों को नौकर की तरह अच्छे वेतन वाली नौकरियाँ देकर अन्य देशों की प्रतिभा का उपयोग उनके विकास के लिए कर रहा है। यदि इस गुणवत्ता को देश के लिए लाभदायक बनाना है तो ऐसे मेधावी छात्रों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार देश में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों को हमारे देश में शुरू करने की आवश्यकता है, इसके लिए शोध पर अधिक जोर देना बहुत जरूरी है। अन्य देशों की तुलना में भारत में शोध न्यूनतम है। समाज के निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक सभी स्तरों के छात्रों की ज्ञान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम फीडबैक दिया गया है और अंततः ऐसा लगता है कि देश का विकास उचित तरीके से होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष स्तर पर अधिक ध्यान दिया गया है या किसी स्तर पर विचार नहीं किया गया है। पिछली नीति के अनुसार छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और छात्रों की रुचि के बीच अंतर के कारण अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से करने में कठिनाइयाँ आ रही थीं, इसलिए छात्रों को रुचि, कला और कौशल के विषय का ज्ञान कैसे दिया जा सकता है, छात्र स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करने में खुशी से भाग लेंगे। जैसा कि इसे डिजाइन किया गया है, निश्चित रूप से छात्र न केवल डिग्री प्राप्त करने के

लिए ज्ञान प्राप्त करेगा बल्कि वह स्वयं भी इस प्रक्रिया में भाग लेगा क्योंकि उसे अपनी रुचि के विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। महात्मा गांधी के विचार के अनुसार, औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया है

शिक्षा प्रक्रिया से एक छात्र बाहर आता है, चाहे उसे नौकरी मिले या न मिले, लेकिन उसके पास जो कौशल है, उससे वह अपना जीवन ठीक से जी सकेगा। पहले की नीति में 102 चरण को अपनाया गया था, नई नीति के अनुसार 5 3 3 4 चरण को अपनाया गया है। संक्षेप में, राज्य सरकार पिछली नीति के अनुसार 12 साल और नई नीति के अनुसार 15 साल के लिए छात्रों की शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर होना चाहिए, जो कि आयोग की तुलना में आज तक का सबसे अधिक है। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों का प्रतिशत 26.3 प्रतिशत है और नए अनुसार आयोग ने वर्ष 2035 तक इसे 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है।

एनईपी 2020 के हिस्से के रूप में, विभिन्न शैक्षिक स्तर पेश किए जाएंगे। मौलिक शिक्षा चरण (आयु समूह 3–8 वर्ष) मौलिक शिक्षा (आयु समूह 3–8 वर्ष) शिक्षा वर्ग आयु नर्सरी 4 वर्ष जूनियर केजी 5 वर्ष सीनियर केजी 6 वर्ष प्रथम मानक 7 वर्ष द्वितीय मानक 8 वर्ष एक बच्चे का मस्तिष्क 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ता है। इस अवधि के दौरान, बच्चा कई नई चीजें सीख रहा होता है, इसलिए 3 वर्ष के बच्चे को शिक्षा धारा में शामिल किया जाता है, लेकिन इस उम्र में, उन्हें किसी भी तरह से किताबी शिक्षा दिए बिना, रुचि के विभिन्न खेलों के माध्यम से ज्ञान देने का उद्देश्य होता है। प्री-प्राइमरी के तीन साल और क्ले 1 और 2 के कुल 5 साल तक, बच्चों की स्कूल में रुचि होगी। इस चरण में, बच्चों की किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इस उम्र के बच्चे अवलोकन के माध्यम से कई चीजों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

प्रारंभिक शिक्षा चरण (आयु वर्ग 9–11 वर्ष) तालिका क्रमांक 02 प्रारंभिक शिक्षा (आयु वर्ग 9–11 वर्ष) शिक्षा वर्ग आयु तीसरी कक्षा 9 वर्ष चौथी कक्षा 10 वर्ष पांचवीं कक्षा 11 वर्ष नई शिक्षा नीति 2020 का दूसरा चरण तीन साल का होगा, यानी तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा में बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा परीक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कि मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थी के विचारों को गति दी जा सकती है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया जाता है। मिडिल शिक्षा (आयु वर्ग 12–14 वर्ष) शिक्षा वर्ग आयु छठी कक्षा 12 वर्ष सातवीं कक्षा 13 वर्ष आठवीं कक्षा 14 वर्ष इसके बाद के 3 वर्षीय चरण यानि छठी, सातवीं और आठवीं में विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम, भारतीय भाषा शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इस चरण में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कला, कौशल और खेल के क्षेत्र में कोई भी शिक्षा लेने की स्वतंत्रता होगी ताकि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में खुशी से भाग ले सकें और यह चरण उसके भावी जीवन की दृष्टि से उसके लिए जीवन जीने का एक तरीका तैयार करेगा।

माध्यमिक शिक्षा चरण (आयु वर्ग 15–18 वर्ष) तालिका क्रमांक 04 माध्यमिक शिक्षा (आयु वर्ग 15–18 वर्ष) शिक्षा वर्ग आयु नौवीं कक्षा 15 वर्ष दसवीं कक्षा 16 वर्ष ग्यारहवीं कक्षा 17 वर्ष बारहवीं कक्षा 18 वर्ष नई शिक्षा नीति 2020 में इसे अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है। इसकी अवधि चार वर्ष की है, अर्थात् कक्षा IX, X, XI और XIIA कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा इस स्थान पर नहीं है बल्कि सेमेस्टर अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है ताकि छात्रों को केवल परीक्षा के लिए अध्ययन करने का महत्व महसूस न हो, जिससे उन बच्चों की संख्या कम होगी जो वर्ष में केवल कुछ समय के लिए अध्ययन करते हैं क्योंकि यह एक वार्षिक परीक्षा है और सेमेस्टर पैटर्न के कारण बच्चे बार-बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इस स्तर पर बच्चों को विदेशी भाषा सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है

स्नातक शिक्षा स्तर, प्रत्येक विषय में तीन या चार वर्षीय स्नातक डिग्री होगी जिसे कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है, जैसे पहले वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा या अध्ययन के तीसरे वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री। चार साल की स्नातक योजना का पालन करने की सिफारिश की जाती है जिसमें एक प्रमुख, मामूली और शोध परियोजनाएं शामिल हैं।

स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर, स्नातक स्तर के बाद अध्ययन के एक और वर्ष को स्नातक अनुसंधान कहा जाएगा। प्रत्येक चरण को पूरा करने के बाद, छात्रों को वर्तमान ग्रेड के अनुसार क्रेडिट मिलेंगे और ये छात्र यूजीसी के अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) को देख पाएंगे। आप इन क्रेडिट का इस्तेमाल नौकरी पाने या आगे की शिक्षा के लिए कर सकते हैं। स्नातकोत्तर अध्ययन की अवधि 1 या 2 वर्ष होगी। यदि छात्र स्नातक के बाद स्नातकोत्तर करना चाहता है तो 2 वर्ष की अवधि और शोध के बाद स्नातकोत्तर के लिए 1 वर्ष की अवधि। और एकीकृत पांच वर्षीय डिग्री वाले छात्रों के लिए, अंतिम वर्ष का जोर अच्छे शोध पर है। मास्टर डिग्री में पेशेवर क्षमता बढ़ाने और छात्रों को शोध डिग्री के लिए तैयार करने के लिए एक बड़ा शोध घटक शामिल होगा।

शोध चरण, पीएचडी शोध चरण में किसी भी मुख्य विषय, बहु-विषयक विषय या अंतः विषयक विषय में पूर्णकालिक अध्ययन के लिए कम से कम तीन से चार साल और अंशकालिक अध्ययन के लिए अलग से अच्छे शोध करने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने चुने हुए पीएचडी क्षेत्र से संबंधित शिक्षाशास्त्र, शिक्षा या शिक्षण में 8-क्रेडिट कोर्स में भाग लेना चाहिए। एक वर्ष का पिछला एमफिल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। आजीवन सीखना NEP 2020 आजीवन सीखने और शोध को बढ़ावा देता है ताकि विकलांग व्यक्ति समाज में सुखद जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अनुभव न खो दें। जीवन के किसी भी चरण में, शिक्षा और शोध को अधिक परिपक्वता और जीवन की खुशी को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है।

NEP बच्चों में साक्षरता और भाषा विकास को बढ़ावा देने में स्कूल पुस्तकालयों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। यह अनुशासक करता है कि प्रत्येक स्कूल में छात्रों की पढ़ाई का समर्थन करने के लिए आयु-उपयुक्त पुस्तकों और संसाधनों

का संग्रह वाला एक पुस्तकालय होना चाहिए। नीति डिजिटल पुस्तकालयों के विकास का भी आह्वान करती है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को शैक्षिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान कर सकती है। पुस्तकालय और शिक्षक शिक्षा एनईपी शिक्षक शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका को भी पहचानती है। यह अनुशंसा करता है कि सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संसाधनों तक पहुंच के साथ एक अच्छी तरह से स्टॉक की गई लाइब्रेरी होनी चाहिए। यह प्रशिक्षु शिक्षकों को शिक्षा में नवीनतम शोध तक पहुंचने और अपने शिक्षण कौशल को विकसित करने में सक्षम करेगा। नीति यह भी अनुशंसा करती है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों को अपने छात्रों के बीच पुस्तकालयों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पुस्तकालय के उपयोग को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके और पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। किताबें स्कूल सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध होनी चाहिए

आईसीटी के अनुप्रयोग को स्कूल के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी शामिल किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को भी स्कूल और सार्वजनिक पुस्तकालयों की जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय और उच्च शिक्षा एनईपी उच्च शिक्षा में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। यह अनुशंसा करता है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संसाधनों तक पहुंच के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय होने चाहिए। नीति अनुसंधान पुस्तकालयों के विकास का भी आह्वान करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विशेष संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। सरकार को वयस्क और आजीवन सीखने की प्रक्रिया के लिए उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए और क्षेत्रीय प्रारूप में सर्वोत्तम पठन सामग्री प्रदान करके सामुदायिक शिक्षण को शामिल करना चाहिए। एनईपी अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने में पुस्तकालयों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता को भी पहचानता है। नीति अनुशंसा करती है कि पुस्तकालयों को संकाय और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अंतःविषय संग्रह विकसित करना चाहिए जो कई क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन कर सकते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालयों ने हमेशा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ज्ञान, संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की है। पुस्तकालयों पर एनईपी की सिफारिशें भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी ढांचा प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करके कि छात्रों को शिक्षा के सभी स्तरों पर अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों तक पहुंच हो। साथ ही सभी रूपों में पुस्तकालय सामग्री को मजबूत करें। पुस्तकालयों पर एनईपी की सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी है। भारत में कई स्कूलों और कॉलेजों में पुस्तकालयों की स्थापना और रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। इसलिए, सरकार और शिक्षा संस्थानों को पुस्तकालयों में निवेश को प्राथमिकता देने और आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। एक और चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पुस्तकालय तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाएँ। डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के विकास के साथ, पुस्तकालयों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

अनुसंधान सहायता के केंद्र के रूप में पुस्तकालय एनईपी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान के मूल्य पर भी जोर दिया। यह सिर्फ सुझाव देता है कि पुस्तकालय ग्राहकों की मांग के अनुसार सभी आवश्यक सेवाओं के साथ तैयार रहें। पुस्तकालय निस्संदेह एक संगठन के शोध प्रयासों का काफी हद तक समर्थन कर सकते हैं। सार्वजनिक और संस्थागत पुस्तकालय अक्सर जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और युवा व्यवसाय मालिकों को धन मुहैया कराते हैं ताकि वे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं की योजना बना सकें और क्रांतियों का एक पूल बना सकें। देश के हर क्षेत्र को आविष्कारकों, महत्वाकांक्षी व्यवसाय मालिकों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अन्य सदस्यों की मदद करने के लिए अनुसंधान का समर्थन करने के लिए कुछ सार्वजनिक और संस्थागत पुस्तकालयों की स्थापना करनी चाहिए। एक अन्वेषक होने के लिए आवश्यक जानकारी, विषय के बारे में अधिक जानने की इच्छा और क्षेत्र में योगदान करने की इच्छा होना आवश्यक है। संदर्भ प्रबंधन और सूचना पुनर्प्राप्ति पर विशेष जोर देने के साथ उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन प्रदान करके, पुस्तकालय शोधकर्ताओं को अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस संबंध में, विशेष पुस्तकालयाध्यक्षता काफी फायदेमंद हो सकती है।

पुस्तकालय अन्य विषयों के अलावा अनुसंधान में विशेष रुचि ले सकते हैं। हमें संदर्भ प्रशासन, सांख्यिकीय विश्लेषण, ओपन-सोर्स तकनीक, अनुसंधान सहायता उपकरण और पुनर्प्राप्ति विधियों में विशेषज्ञता वाले एक अलग अनुसंधान लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के अपने लक्ष्यों में अनुसंधान लाइब्रेरियन होने के महत्व पर जोर दिया गया है। एनआईआरएफ पारंपरिक अनुसंधान निधि संगठनों के अलावा अनुसंधान गतिविधियों को वित्तपोषित और प्रबंधित करेगा। अनुसंधान लाइब्रेरियन एनआईआरएफ को एक नोडल अधिकारी के रूप में अपनी निष्पक्षता बनाए रखने में मदद कर सकता है। हाल ही में, INFLIBNET ने भारतीय विश्वविद्यालयों और संगठनों द्वारा किए जा रहे शोध परियोजनाओं को उजागर करने और व्यवस्थित करने के लिए प्लैटफॉर्म बनाई। IRNSI के मूल्य में सुधार करने के लिए, कई लाइब्रेरियन नोडल अधिकारियों के रूप में विद्वानों की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाने में विश्वविद्यालय की सहायता करना। उन्हें संदर्भ पुस्तकों और उच्च-क्षमता वाली पाठ्यपुस्तकों के लिए एक सुव्यवस्थित भंडार के रूप में काम करना चाहिए। चूंकि उन्हें प्रत्येक विषय क्षेत्र से संबंधित होने के लिए प्रत्येक विषय अनुशासन के बारे में कम से कम थोड़ा समझना चाहिए, इसलिए लाइब्रेरियन को एक शिक्षक के रूप में संदर्भित किया गया है।

छात्रों को सहायता प्रदान करें। पुस्तकालय NEP 2020 की सफलता के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे ई-पुस्तकें, पत्रिकाएँ और धारावाहिक प्रकाशनों के साथ-साथ वेब-आधारित डेटाबेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रदान करते हैं। पुस्तकों, ऑडियोटेप और वीडियो जैसे मौजूदा संसाधनों के डिजिटलीकरण पर जोर देने के अलावा, NEP ने शैक्षिक प्रणाली के चार तत्वों पर जोर दिया। पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, चल रहे मूल्यांकन और छात्र सहायता। मूल संस्थान महत्वपूर्ण छात्र सहायता सुविधाएँ स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी होगा कि उनके पास अपनी क्षमताओं और दक्षता में सुधार

करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। पुस्तकालयों में प्रौद्योगिकी एकीकरण और उपयोग जब आईसीटी को लागू करने और कई क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने की बात आती है, तो भारत ने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बदौलत अब पूरा देश डिजिटल रूप से सशक्त है और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जब प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाता है, तो शिक्षा विकास को चार गुना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी और शिक्षा एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं और परस्पर लाभकारी हैं। इन सेवाओं की गेटकीपिंग और उपयोगकर्ता अनुरोधों को पूरा करने के लिए तकनीकी परिवर्तनों की निरंतर गति के साथ बने रहने के लिए योग्य और अनुभवी पेशेवरों की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण ने शैक्षणिक प्रथाओं को उन्नत किया है और शैक्षिक प्रणाली के कई पहलुओं को बढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी (NETF) को वर्तमान शिक्षण और सीखने की तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और तैनाती पर दो-तरफा संचार के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए NEP के अंदर एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। NETF शिक्षा में प्रौद्योगिकी के निर्माण, उपयोग और प्रशासन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करेगा। डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए, NETF डेटा का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ताओं के एक विविध समूह के साथ काम करते हुए कई स्रोतों से डेटा की एक स्थिर धारा का उपयोग करेगा। बढ़ते डिजिटल डिवाइड और इसके मुद्दों को संबोधित करने के लिए, पुस्तकालय हाइब्रिड और डिजिटल में विकसित हुए हैं और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को एकीकृत किया है। शिक्षण और सीखने के लिए सामग्री तक पहुँच प्रदान करके, फिर कार्यान्वयन का पता लगाना। आजीवन सीखने के लिए एक मंच के रूप में पुस्तकालय संस्थान से केवल औपचारिक शिक्षा ही उपलब्ध है। जब किसी ने उचित शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। पुस्तकालयों का उपयोग करना प्रभावी है। यह कभी भी जाति, पंथ या यौन अभिविन्यास को इस बात के मानदंड के रूप में खारिज नहीं करता है कि कोई व्यक्ति नियमित छात्र है या नहीं। पुस्तकालयों में छात्र की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पठन सामग्री होती है। कक्षा निर्देश की आयु सीमा और अवधि निर्धारित की जाती है। परिणामस्वरूप, पुस्तकालयों का आजीवन सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आजीवन सीखने की प्रेरणा काम, अनुभव, जुनून और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रभावित होती है

पर्याप्त पुस्तकालय कर्मचारी NEP 2020 से, शिक्षकों, छात्रों और आम जनता के लिए पुस्तकालय सेवाओं का प्रबंधन करने के साथ-साथ उनके लिए उपयुक्त कैरियर पथ और ब्लू डिजाइन करने के लिए पर्याप्त पुस्तकालय कर्मचारियों का होना महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में मौजूद सभी पुस्तकालयों को मजबूत किया जाएगा, ग्रामीण पुस्तकालयों और वाचनालयों को वंचित क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री व्यापक रूप से सुलभ होगी, बच्चों के पुस्तकालय और मोबाइल पुस्तकालय खोले जाएंगे, पूरे भारत में और सभी विषय क्षेत्रों में सामाजिक पुस्तक क्लब स्थापित किए जाएंगे, और शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में यह भी कहा गया है कि पुस्तकालयों को सभी क्षेत्रों के पाठकों के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का भंडार रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि स्कूलों और संगठनों में पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त स्थान

और सुविधाओं की कमी है। परिणामस्वरूप, 2025 तक उपयोगकर्ता के अनुकूल संसाधनों के साथ एक सुव्यवस्थित स्थान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि पुस्तकालयों को आम जनता और समाजों के लिए एक नया प्रकार का मूल्य दिया जा सके। पुस्तकालय के लिए उपयुक्त अवसंरचनाओं में शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी इच्छुक वयस्कों को वयस्क शिक्षा, अध्ययन और आजीवन सीखने की सुविधा प्राप्त हो, उचित और स्वीकार्य अवसंरचना सुनिश्चित की जाएगी। वयस्क शिक्षा कक्षाओं के लिए स्कूलों, स्कूल परिसरों और सार्वजनिक पुस्तकालयों का उपयोग करना जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं, साथ ही साथ अन्य सामुदायिक जुड़ाव और संवर्धन गतिविधियाँ, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। भौतिक और मानव संसाधनों का कुशल उपयोग और शिक्षा के इन पाँच रूपों और उससे आगे के बीच तालमेल का निर्माण स्कूल, उच्च, लेखा परीक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ अन्य सामुदायिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के लिए बुनियादी ढाँचे के साझाकरण पर निर्भर करेगा। इन कारकों के कारण, वयस्क शिक्षा केंद्र (AECS) अन्य सार्वजनिक संगठनों जैसे भूमे, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं।

अनुसंधान और विकास के लिए पुस्तकालयों पर पुनर्विचार अनुसंधान और विकास के साथ-साथ विद्वानों के संचार वातावरण को बढ़ाने को NEP 2020 के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छम्ह में बड़े डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ने और संदर्भ सेवाओं के माध्यम से, पुस्तकालय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन सरकार एनईपी 2020 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों को विकसित करने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें नीति के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, नीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य और समयसीमा स्थापित करना और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना शामिल है। वित्त पोषण और निवेशरू सरकार एनईपी 2020 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण और निवेश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना, बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराना और शिक्षा में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का समर्थन करना शामिल है।

निष्कर्ष सरकार आधुनिक और लचीले पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए जिम्मेदार है जो NE 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, नया पाठ्यक्रम विकसित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पाठ्यक्रम 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप हो। NEP नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सरकार की भूमिका वित्त पोषण और निवेश पाठ्यक्रम विकास शिक्षक प्रशिक्षण और विकास निगरानी और मूल्यांकन। शिक्षक प्रशिक्षण और विकासरू यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षकों के पास उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान

है, सरकार प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, शिक्षकों को चल रहे व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रशिक्षकों का नियमित रूप से मूल्यांकन और प्रशिक्षण किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकनरु सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है कि नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। इसमें निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा स्थापित करना, हितधारकों से डेटा और प्रतिक्रिया एकत्र करना और नीति के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। इसमें स्कूलों, शिक्षक शिक्षा संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों के विकास का आह्वान किया गया है। नीति यह मानती है कि पुस्तकालय सीखने और शोध के केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं, पुस्तकों, पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया सहित संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। पुस्तकालयों पर एनईपी की सिफारिशें भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की रूपरेखा प्रदान करती हैं। सरकार को पुस्तकालय कर्मचारियों की जरूरतों को स्वीकार करना चाहिए और पुस्तकालयों से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की पूर्ति करनी होगी। समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, लचीली और बहुभाषी शिक्षा, प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर नीति का ध्यान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 अग्रवाल निधि और झा बबीता (2021) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के डिजीटलीकरण से विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन सोशल साइंसेज, 9(1) पृष्ठ 27–33
- 2 ऐथल पी. एस. और ऐथल शुभ्रज्योत्सना (2020) भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एंड सोशल साइंसेज (आईजेएमटीएस), खंड 5 (2), पृष्ठ 19–41
- 3 आकाश वर्मा (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्कूली शिक्षा पर प्रभाव। बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा खंड 11(4), पृष्ठ 71–75
- 4 आशुतोष गौड़ (2022) भारत की नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लिए एक रोडमैप। रिसर्च गेट.खंड 21 (12), पृष्ठ 632–637
- 5 आसिफ मोहम्मद और सिंह के. के. (2022) भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत पुस्तकालय। आईपी इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7(1) पृष्ठ 18

- 6 अविनाश कुमार सिंह (2022) उच्च शिक्षा में नीति की भूमिका एनईपी 2020 की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, इग्नू, नई दिल्ली। पृष्ठ 12
- 7 बापते विशाल दत्तात्रेय (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में पुस्तकालय लाइब्रेरी और सूचना अध्ययन के इतिहास. खंड 69, पृष्ठ 224
- 8 भारती मुकेश चंद (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और पुस्तकालयों का महत्व। पृष्ठ 78
- 9 बिजल मिस्त्री (2022) एनईपी 2020 की विश्लेषणात्मक समीक्षा। बहुभाषी सभी विषयों में अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल खंड 10 (2), पृष्ठ 13